# लक्ष्य और उपलब्धियां

## प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2014 का संबोधन

# पूरे किए गए वादे - उपलब्धि

## 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन

| क्र.सं. | वादे | उपलब्धि |
|---|---|---|
| 01 | **जन धन योजना**<br>यह योजना एक नया मार्ग प्रशस्त करेगी। अत: 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' के तहत किसी भी खाता धारक को एक डेबिट कार्ड दिया जाएगा। हर गरीब परिवार को उस डेबिट कार्ड के साथ एक लाख रुपये के बीमे की गारंटी दी जाएगी, ताकि उनके जीवन में जब कोई गंभीर संकट आए तो एक लाख रुपये के बीमे से इस तरह के परिवारों की समुचित आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। | • प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत 19 जुलाई, 2017 तक कुल मिलाकर 29.18 करोड़ खाते खोले गए हैं। इनमें से 17.45 करोड़ खाते 19 जुलाई, 2017 तक ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं।<br>• 19 जुलाई, 2017 तक शहरी क्षेत्रों में खोले गए पीएमजेडीवाई खातों की संख्या: 11.73 करोड़<br>• 22.53 करोड़ रुपे कार्ड जारी किए गए (19 जुलाई, 2017 तक)<br>• 15.77 करोड़ सक्रिय खातों को 'आधार' से लिंक किया गया (असम और मेघालय को छोड़कर)<br>जन धन खातों में कुल जमा धनराशि = 64,777 करोड़ रुपये (19 जुलाई, 2017 तक) |

| | | |
|---|---|---|
| 02 | **मेक इन इंडिया**<br><br>मैं लाल किले की प्राचीर से विश्व भर के लोगों से यह अपील करता हूं 'आओ, भारत में बनाओ', 'आओ, भारत में निर्माण करो'। चाहे दुनिया के किसी भी देश में बेचो, लेकिन निर्माण यहीं करो। हमारे पास कुछ भी करने के लिए आवश्यक कौशल, प्रतिभा, अनुशासन और दृढ़संकल्प है। हम दुनिया को यहां अनुकूल अवसर देना चाहते हैं, जो यहां सुलभ है। 'आओ, भारत में निर्माण करो' और हम पूरी दुनिया से यही कहेंगे, विद्युत से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, 'आओ, भारत में निर्माण करो', ऑटोमोबाइल से लेकर कृषि मूल्यवर्द्धन तक, 'आओ, भारत में निर्माण करो', कागज हो या प्लास्टिक, 'आओ, भारत में निर्माण करो', उपग्रह हो या पनडुब्बी, 'आओ, भारत में निर्माण करो'। हमारा देश काफी सामर्थ्यवान है। | भारत में विनिर्माण एवं निवेश को काफी बढ़ावा देने की एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल के रूप में 'मेक इन इंडिया' ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के क्षेत्र में अनगिनत सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया है। इससे देश में निवेश का माहौल अनुकूल हो गया है। देश में एफडीआई के प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल, 2014 से लेकर मार्च, 2017 तक की अवधि के दौरान कुल मिलाकर 161 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आया है। यह एफडीआई प्रवाह विशेष मायने रखता है क्योंकि अप्रैल 2000 से लेकर मार्च 2017 तक भारत में आये कुल एफडीआई का 33.2 प्रतिशत हिस्सा इसी छोटी अवधि में आया है। यही नहीं, मेक इन इंडिया के शुभारंभ से लेकर अब तक देश में एफडीआई के प्रवाह में 62 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।<br>मेक इन इंडिया का शुभांकर 'शेर' जिस तरह बड़े गर्व से आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए पूरी दुनिया भी इसकी कामयाबी से अचंभित है। भारत को ए.टी. कियर्ने के एफडीआई विश्वास सूचकांक में 8वीं रैंकिंग दी गई है। भारत को दुनिया के सर्वाधिक आकर्षक निवेश गंतव्यों में पहली रैंकिंग प्रदान की गई है। इसी तरह भारत को दुनिया भर में मतदान के बाद 110 निवेश गंतव्यों में पहले पायदान पर रखा गया है। निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से दुनिया के सर्वोत्तम देशों में भारत को प्रथम रैंकिंग प्रदान की गई |

| | | |
|---|---|---|
| | | है। नई परियोजनाओं में एफडीआई की दृष्टि से भी भारत शीर्ष गंतव्य है। मेक इन इंडिया एक ऐसा विश्वसनीय ब्रांड बन गया है जो कमोबेश हर तरफ नजर आता है और इससे निवेश के नये द्वार खुल गये हैं। ये सभी रैंकिंग भारत की आर्थिक संभावनाओं के प्रति निवेशकों के अटूट विश्वास को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। सरकार भारत को निवेशक अनुकूल गंतव्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कारोबार में सुगमता के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों से लेकर एफडीआई संबंधी नीतिगत व्यवस्था में जो भी सुधार लागू किये गए हैं उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। देश में बेहतर कारोबारी माहौल की पुष्टि भारतीय उद्योग परिसंघ का व्यावसायिक विश्वास सूचकांक भी करता है, जो वित्त वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही में बढ़कर 64.1 अंक के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। |
| **03** | **कौशल भारत**<br><br>यदि हमें अपने देश को तेजी से विकास के पथ पर ले जाना है तो हमारा मिशन होना चाहिए 'कौशल विकास' और 'कुशल भारत'। भारत के करोड़ों युवाओं को अपना कौशल बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए और इसके लिए देश भर में पुरातन प्रणालियों के बजाय एक समुचित नेटवर्क होना चाहिए। इन युवाओं को ऐसे कौशल की प्राप्ति | • पिछले तीन वर्षों में अब तक कुल मिलाकर 2.6 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। इनमें से 1.17 करोड़ लोगों को अकेले एमएसडीई के कार्यक्रमों के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया गया है।<br>**<u>प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना:</u>**<br>• पीएमकेवीवाई के तहत 30 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को या तो प्रशिक्षित कर दिया गया है |

| | | |
|---|---|---|
| | पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने में भरपूर योगदान दे सके। जब भी वे दुनिया के किसी भी देश में जाएं तो उनके कौशल की अवश्य ही सराहना होनी चाहिए। हम द्विआयामी विकास के लिए प्रयास करना चाहते हैं। | या प्रशिक्षित किया जा रहा है। लगभग 17 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए 3300 से ज्यादा प्रशिक्षण केंद्रों को अतिरिक्त लक्ष्य दिए गए हैं।<br>• 30 लाख अभ्यर्थियों में से 5,50,877 को पूर्व प्रशिक्षण मान्यता (आरपीएल) कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति में मौजूद बुनियादी कौशल का आकलन किया जाता है तथा योग्यता के एक विशेष स्तर तक उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। यह असंगठित क्षेत्र को औपचारिक स्वरूप प्रदान करने में मदद करेगा।<br>• वर्तमान में पीएमकेवीवाई के तहत 34 क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।<br>• यह योजना 30 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही है।<br>**<u>प्रधानमंत्री कौशल केंद्र:</u>**<br>• 556 पीएमकेके का आवंटन किया गया है, जो 514 जिलों को कवर करता है। इनमें से 212 केंद्र परिचालन के लिए तैयार हैं। हमने देश भर |

| | | |
|---|---|---|
| | | में 600 पीएमकेके खोलने का लक्ष्य रखा है, जो मार्च, 2018 के आखिर तक लगभग प्रत्येक जिले और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को कवर कर लेंगे।<br>**<u>राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप संवर्द्धन योजना</u>**<br>• इस योजना के शुभारंभ के 10 माह के भीतर 6.4 लाख से ज्यादा प्रशिक्षुओं और 32,281 प्रतिष्ठानों को एनएपीएस के तहत पंजीकृत किया गया है।<br>**<u>शैक्षणिक तुल्यता सुनिश्चित करना :</u>**<br>• एनआईओएस के एक ब्रिज मॉड्यूल के जरिए 10वीं/12वीं कक्षा के साथ आईटीआई विद्यर्थियों की शैक्षणिक तुल्यता सुनिश्चित की गई है। 1027 आईटीआई विद्यार्थियों का प्रथम बैच दिसंबर, 2016 में आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ था।<br>**<u>दीर्घकालिक कौशल विकास में क्षमता निर्माण :</u>**<br>• 5 आईआईएस (भारतीय कौशल संस्थान) प्रस्तावित हैं और आईआईएस कानपुर की आधारशिला प्रधानमंत्री ने 9 दिसंबर, 2016 को |

| | | |
|---|---|---|
| | | कानपुर में रखी थी।<br>• एटीआई/एफटीआई की संख्या बढ़ाकर 14 एटीआई/एफटीआई कर दी गई है, जो 12 राज्यों में फैले हुए हैं। इसके अलावा, महिलाओं पर केंद्रित 5 नए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (आरवीटीआई) भी खोले गए हैं।<br>**<u>अन्य उपलब्धियां :</u>**<br>• 1.17 करोड़ अभ्यर्थियों को 2015-17 के दौरान एमएसडीई कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित किया गया।<br>• औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में सीटों की संख्या में 44 प्रतिशत की वृद्धि की गई।<br>• एनएसडीसी के अल्पकालिक शुल्क आधारित कौशल विकास मॉडल के तहत वर्ष 2014 में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तुलना में वर्ष 2017 में इस तरह के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या में 600 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। अब तक एक करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित |

| | | |
|---|---|---|
| | | किया गया है।<br>• वर्ष 2016-17 के दौरान कौशल विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सीएसआर के तहत उद्योगों की ओर से 100 करोड़ से भी ज्यादा की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।<br>• राज्यों में कौशल विकास को मजबूती प्रदान करने के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं संकल्प (4000 करोड़) और स्ट्राइव (2200 करोड़) का शुभारंभ किया गया।<br>• नौकरियों में विश्व स्तर पर गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र (आईआईएससी) खोले गए। इस तरह के 14 केंद्रों में परिचालन शुरू हो गया है। वर्ष 2018 तक 100 केंद्र खोले जाने हैं। कौशल के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिए 11 देशों के साथ भागीदारी की गई है।<br>• युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना का शुभारंभ किया गया।<br>ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2015 में 8 उत्कृष्टता |

| | | |
|---|---|---|
| | | पदक जीते, 28 लोगों की टीम अबुधाबी में आयोजित होने वाले वर्ल्ड स्किल्स 2017 में भाग लेगी। |
| **04** | **डिजिटल इंडिया**<br>मेरा यह कहना है कि आज आईटी ही एक ऐसा साधन है जो देश के प्रत्येक नागरिक को आपस में कनेक्ट करने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि हम 'डिजिटल इंडिया' की मदद से एकता के मंत्र को साकार करना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, यदि हम इन सभी के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुझे पक्का भरोसा है कि 'डिजिटल इंडिया' में पूरी दुनिया के साथ बराबरी के स्तर पर खड़े होने की क्षमता होगी। हमारे देश के युवाओं में यह क्षमता है, यह उनके लिए एक अवसर है? | **स्तंभ - 1 : ब्रॉडबैंड हाईवे**<br>- भारतनेट परियोजना के तहत, 30 जुलाई 2017 तक 1,07,066 जीपी में 2.40 लाख किलोमीटर लंबी पाईपलाइन बिछाई गई, 1,00,322 जीपी के लिए 2.22 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया और 26,548 जीपी को जोड़ा गया है।<br>**स्तंभ - 2 : मोबाइल संपर्कता के लिए व्यापक पहुंच** (वित्त वर्ष 2014-18 के दौरान 42,300 गांवों को शामिल करने का लक्ष्य)<br>- ग्रामीण टेली-घनत्व - 56.98 प्रतिशत (30 अप्रैल, 2017 के अनुसार)<br>- **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विस्तृत दूरसंचार विकास योजना :** सरकार द्वारा मंजूर की गई इस परियोजना का लक्ष्य 8621 चयनित वंचित गांवों को मोबाइल संपर्क उपलब्ध कराना है। |

| | | |
|---|---|---|
| | | - **वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संचार सेवा :** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संचार सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इस परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है।<br>- **अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना :** अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के लिए मोबाइल संपर्कता के प्रावधान सहित एक व्यापक दूरसंचार विकास योजना के लिए दूरसंचार आयोग ने अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है।<br>**स्तंभ - 3 : सार्वजनिक इंटरनेट संपर्क कार्यक्रम**<br>- देशभर में 3,00,774 साझा सेवा केंद्र (सीएससी) पंजीकृत किए गए है, जिसमें से 1,96,922 केंद्र ग्राम पंचायत स्तर पर हैं। कुल पंजीकृत साझा सेवा केन्द्रों में से 2,61,071 सीएससी सक्रिय हैं |

| | | |
|---|---|---|
| | | और ई सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें से 1,63,226 केंद्र ग्राम पंचायत स्तर पर हैं।<br>- लगभग 23,242 डाकघरों में सीबीएस प्रणाली शुरू की गई है।<br>- पोस्टल एटीएम की संख्या 976<br>- 900 ई-कॉमर्स कंपनियों से हाथ मिलाया गया।<br>**स्तंभ - 4 : ई-गवर्नेंस : सुधार के कार्य**<br>- अबतक केंद्र सरकार के 38 मंत्रालयों / विभागों के माध्यम से 220 से भी अधिक केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए लाभार्थियों के आधार लिंक करने हेतु आधार अधिनियम 2016 का इस्तेमाल करते हुए 128 से अधिक अधिसूचनाएं प्रकाशित की गई हैं<br>कुछ प्रमुख योजनाओं में आधार लिंक करने के संदर्भ में मौजूदा स्थिति का विवरण नीचे दी गई है - |

| | | |
|---|---|---|
| | | **31 जुलाई 2017 को राष्ट्रव्यापी स्थिति (करोड़ में)** |

| | कुल लाभांवितों की संख्या | आधार से लिंक | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| **नरेगा (सक्रिय)** | 10.76 | 8.56 | 79.61% |
| **एनएसएपी** | 2.82 | 0.64 | 22.77% |
| **डीबीटीएल** | 20.94 | 18.29 | 87.35% |
| **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन कार्ड)** | 23.16 | 18.05 | 77.93% |
| **पीएमजेडीवाई** | 28.44 | 18.97 | 66.69% |
| **ईपीएफओ** | 11.62 | 1.79 | 15.36% |

| | | |
|---|---|---|
| | | 116 करोड़ से अधिक निवासियों का<br><br>- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण - 51 मंत्रालयों / विभागों की 315 योजनाएं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के दायरे में है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 2.14 लाख करोड़ रूपये से अधिक धनराशि अंतरित की गई है और मंत्रालयों / विभागों से जानकारी मिली है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के प्रारूप में योजनाएं लागू होने से पिछले तीन वर्षों में 57,029 करोड़ रूपये की बचत हुई है।<br>- ई-ऑफिस के लिए उपभोक्ता विभागों की संख्या 263 है।<br>**स्तंभ - 5 : ई-क्रांति - सेवाओं का इलैक्ट्रोनिक वितरण** (सभी एमएमपी विभागों को शामिल करने का लक्ष्य)<br>- ई-क्रांति के तहत 44 मिशन परियोजनाओं के |

| | | |
|---|---|---|
| | | माध्यम से 3438 ई-सेवाएं उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान प्रतिमाह औसतन 101.80 करोड़ लेन-देन के साथ 1221.68 करोड़ से अधिक इलैक्ट्रोनिक लेन-देन किए गए।<br><br>**स्तंभ - 6 : सबके लिए सूचना**<br><br>**MyGov प्लेटफॉर्म :** MyGov प्लेटफॉर्म पर 45 मंत्रालयों की सक्रिय भागीदारी से 'काम करो, विमर्श करो और प्रसारित करो' की मूल अवधारणा के जरिए नागरिकों के साथ पहूंच कायम की जा रही है। फिलहाल MyGov प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विभिन्न क्रियाकलापों में भागीदारी करते हुए MyGov प्लेटफॉर्म के साथ 45.28 लाख उपभोक्ता पंजीकृत है। MyGov प्लेटफॉर्म से जुड़े क्रियाकलाप 61 ग्रुपों में संरचित हैं, जिसमें 660 कार्य, 728 विमर्श, 238 मतदान / सर्वेक्षण और 148 वार्ताएं शामिल है।<br><br>**सरकारी डाटा प्लेटफॉर्म :** इस पोर्टल पर लक्ष्य भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों द्वारा आम लोगों के इस्तेमाल के लिए सरकारी संगठनों से संबंधित डाटा सेटों, दस्तावेजों, सेवाओं, उपायों और औजारों को प्रकाशित करना है। 105 मंत्रालयों / विभागों (81 |

| | | |
|---|---|---|
| | | केंद्रीय और 24 राज्यों से) द्वारा 4189 कैटलॉगों के अधीन 1,06,372 से भी अधिक संसाधन प्रकाशित किए गए हैं।<br><br>**स्तंभ - 7 : इलैक्ट्रोनिक्स विनिर्माण**<br><br>'नेट जीरो' आयात का लक्ष्य<br><br>- 4 अगस्त 2017 के अनुसार, अबतक 1.64 लाख करोड़ रूपये के निवेश के प्रस्ताव सहित संशोधित विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम (एमएसआईपी) के अधीन 292 निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं। 21,392 करोड़ रूपये के प्रस्तावित निवेश वाले 106 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं।<br><br>- 20 जुलाई 2017 के अनुसार, इलैक्ट्रोनिक्स विनिर्माण क्लस्टरों के अधीन 12 राज्यों में 1847 करोड़ रूपये की लागत वाली इलैक्ट्रोनिक विनिर्माण परियोजनाओं की स्थापना के लिए 15 आवेदन मंजूर किए गए हैं। इन इलैक्ट्रोनिक विनिर्माण क्लस्टरों का लक्ष्य 33,340 करोड़ |

| | | |
|---|---|---|
| | | रूपये के निवेश को आकर्षित करना है और 1.80 लाख रोजगार के अवसर जुटाने हैं। इनमें से 6 इलैक्ट्रोनिक विनिर्माण क्लस्टरों के लिए 102 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की गई है।<br>- पिछले दो वर्षों में मोबाइल हैण्डसेट और उसके पुर्जे के निर्माण के लिए लगभग 70 कारखाने स्थापित किए गए हैं।<br>- मोबाइल हैण्डसेटों का उत्पादन वर्ष 2014-15 में लगभग 6 करोड़ से तिगुना होकर वर्ष 2016-17 में 17.5 करोड़ हो गया ।<br>• इसी अवधि के दौरान मुल्य के रूप में मोबाइल हैण्डसेट का उत्पादन चार गुना से भी अधिक बढ़कर लगभग 19,000 करोड़ रूपये से 90,000 करोड़ रूपये हो गया है।<br>उपलब्धियां<br>• आधार का दायरा 61 करोड़ (वर्ष 2013-14 में) से बढ़कर 116.30 करोड (24.07.2017 को) पहुंचा। |

| | | |
|---|---|---|
| | | • इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 24.3 करोड़ (जून 2014 में) से बढ़कर 50 करोड़ (मई 2017 में) तक पहुंची।<br>• मोबाइल फोन के उपभोक्ताओं की संख्या 90 करोड़ (जून 2014) से बढ़कर 108 करोड़ (मई 2017) तक पहुंची।<br>• जन-धन खाते की संख्या वर्ष 2014 के 10.44 करोड़ से बढ़कर जुलाई 2017 में 29.09 करोड़ हो गई।<br>• 2014 में प्रतिवर्ष 357 करोड़ से अधिक इलैक्ट्रॉनिक लेन-देन (प्रतिमाह औसतन 29.4 करोड़ लेन-देन) की संख्या 30 जून 2017 को 805 करोड़ (प्रतिमाह औसतन 134 करोड़ लेन-देन) हो गई।<br>• एनओएफएन / भारतनेट के अधीन ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) की लंबाई 2014 की 358 किलोमीटर से बढ़कर जुलाई 2017 में 2,05,404 किलोमीटर हो गई।<br>• अस्पतालों में ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट प्रणाली के तहत बुक की गई अप्वाइंटमेंटों की संख्या 2015-16 के 1,30,555 से बढ़कर जुलाई 2017 में 8,11,541 हो गई। इस सुविधा से युक्त अस्पतालों की संख्या वर्ष 2015-16 में 32 से बढ़कर |

| | | |
|---|---|---|
| | | जुलाई 2017 में 106 हो गई।<br>• ई-हॉस्पिटल के तहत बुक की गई नियुक्तियों की संख्या वर्ष 2015-16 की 12,47,313 से बढ़कर जुलाई 2017 में 88,59,270 हो गई। इस सुविधा से युक्त अस्पतालों की संख्या वर्ष 2015-16 की 4 से बढ़कर जुलाई 2017 में 95 हो गई।<br>• 9 अगस्त 2016 को शुरू की गई गवर्नमेंट ई-मार्केट (जीईएम) प्लेस के तहत खरीददारों, विक्रेताओं और सेवाप्रदाताओं की संख्या वर्ष 2016 की क्रमश: 1969, 4597 और 133 से बढ़कर जुलाई 2017 में क्रमश: 4924, 15640 और 3048 हो गई।<br>• जीवन प्रमाण के तहत पेंशनधारियों और प्रक्रिया में शामिल डीएलसी की संख्या 01 नवंबर, 2014- 31 अक्टूबर, 2015 की क्रमश: 6,01,649 और 4,34,592 से बढ़कर 01 नवंबर, 2016 -17 जुलाई तक क्रमश: 63,79,887 और 43,18,480 हो गई।<br>• डिजिटल लॉकर प्रणाली के तहत पंजीकृत उपभोक्ताओं की |

| | | |
|---|---|---|
| | | संख्या वर्ष 2015-16 में 11.23 लाख से बढ़कर 18 जुलाई, 2017 तक 75.35 लाख हो गई है। अपलोड किए गए दस्तावेजों की संख्या 2015-16 में 19.36 लाख से बढ़कर 18 जुलाई, 2017 तक 90.59 लाख हो गई है।<br>• डिजिटल साक्षरता के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 01 नवंबर, 2014 - 31 अक्टूबर, 2015 की 32,75,852 से बढ़कर 01 नवंबर, 2016 - 30 जून तक 17,94,984 हो गई।<br>• डिजिटल भुगतान संवर्धन के अधीन :<br>o मोबाइल वॉलेटों की संख्या वित्त वर्ष 2016-17 की 990.57 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2017-18 में 2410.72 लाख हो गई।<br>o यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस वित्त वर्ष 2016-17 की 1.0 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2017-18 में 90.36 लाख हो गई।<br>o डेबिट कार्डों (रूपे) की संख्या वित्त वर्ष 2016-17 की 1400.59 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2017-18 में |

| | | |
|---|---|---|
| | | 2670.51 लाख हो गई।<br>○ त्वरित भुगतान प्रणाली (आईएमपीएस) की संख्या वित्त वर्ष 2016-17 की 420.09 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2017-18 में 660.70 लाख हो गई ।<br>○ आधार संवर्द्धित भुगतान प्रणाली (भीम आधार सहित) वित्त वर्ष 2016-17 की 20.57 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2017-18 में 60.36 लाख हो गई।<br>○ पीओएस मशीनों की संख्या 2016-17 की 15 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2017-18 में 31.87 लाख हो गई। |

| | | |
|---|---|---|
| **05** | **स्वच्छ भारत अभियान**<br>यदि सवा सौ करोड़ देशवासी यह निर्णय लेते हैं कि वे कभी गंदगी नहीं फैलाएंगे तो विश्व की किस शक्ति में क्षमता है कि हमारे शहरों और गांवों में गंदगी फैला सके। क्या हम इतना संकल्प नहीं कर सकते? | • मिशन लांच किए जाने के समय से 4.52 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनाए गए।<br>• 31 जुलाई, 2017 तक 2,17,210 गांवों, 155 जिलो और 5 राज्यों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया।<br>• व्यक्तिगत शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 12000 रुपये कर दी गई है।<br>• 02.10.2014 से 02.10.2015 के बीच 80 लाख शौचालय बनाए |

| | | |
|---|---|---|
| | भाइयो और बहनों, 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जंयती होगी। हम महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ कैसे मनाएं? महात्मा गांधी, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दी, जिन्होंने विश्व में ऐसे बड़े देश को सम्मान दिलाया हम उस महात्मा गांधी को क्या देंगे? भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी हृदय से साफ-सफाई और स्वच्छता चाहते थे। क्या हम यह संकल्प ले सकते हैं कि महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ 2019 तक हम अपने गांव, शहर, गली, इलाका, स्कूल, मंदिर और अस्पताल में गंदगी नहीं रहने देंगे? तो यह काम केवल सरकार से नहीं होता बल्कि लोगों की भागीदारी से होता है। इसलिए हमें यह काम मिलकर करना है। | गए। अनुमान 60 लाख शौचालय बनाने का था।<br>• 2014-15 के लिए 50 लाख व्यक्तिगत शौचालय बनाने का लक्ष्य तय किया गया था और 58,54,987 शौचालय बनाए गए। यह लक्ष्य से 117 प्रतिशत अधिक की उपलब्धि है।<br>• 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः 45.59 लाख तथा 49.76 लाख शौचालय बनाए गए। दूसरी ओर एनडीए सरकार के पहले दो वर्षों में यानी 2014-15 तथा 2015-16 (29.02.2015 तक) में क्रमशः 58.54 लाख तथा 97.73 लाख शौचालय बनाए गए।<br>• ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के 100 स्वच्छ प्रतीक स्थानों पर विश्व मानकों के अनुरूप उच्च स्तर की स्वच्छता रखी जाएगी। इन स्थानों में से 20 का चयन चरण-1 और चरण-2 में किया गया है।<br><br>पांच राज्यों के 22 जिलों के गंगा किनारे के 4480 गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया गया। |
| **06** | **सांसद आदर्श ग्राम योजना** | • माननीय सांसदों ने चरण-1 के अंतर्गत 703 ग्राम पंचायतों को गोद लिया और चरण-2 के अंतर्गत 382 ग्राम पंचायतों को गोद लिया और अभी तक 47 ग्राम पंचायतों को अपनाया है।<br>• एसएजीवाई पोर्टल पर राज्यों द्वारा अपलोड की गई रिपोर्टों के |

| | | |
|---|---|---|
| | | अनुसार लागू की जाने वाली 40962 परियोजनाओं में से 21926 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं या प्रगति पर हैं। |
| **07** | **नीति आयोग** | **लक्की ग्राहक योजना तथा डीजी-धन व्यापार योजना**<br>• पूरे देश में उपभोक्ताओं और व्यापारियों सहित 16 लाख विजेताओं ने 258 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि जीती।<br>**डीजी-धन मेला**<br>• मेला 25 दिसंबर, 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा लांच किया गया। मेले देश के 100 शहरों में 100 दिनों तक चले।<br>• 27 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 100 ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कम से कम 15000 संस्थान कैशलेस बने।<br>• नगरों, छोटे शहरों तथा गांव में लगे मेलों में 15 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने से लाखों लोगों को नए खाते खोलने और नया आधार कार्ड बनाने में मदद मिली।<br>**अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) तथा स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (एसईटीयू)**<br>• अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना : दिसंबर, 2016 में 257 शीर्ष विद्यालयों को एटीएल अनुदान दिए गए।<br>• अटल इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना : 60 आवेदक शॉर्टलिस्ट किए |

| | | |
|---|---|---|
| | | गए। अंतर मंत्रालय समूह की सिफारिश के आधार पर चयनित आवेदक पर अंतिम राउंड में एसएससी द्वारा विचार किया जाएगा।<br>• स्थापित इंक्यूबेशन केंद्रों को समर्थन बढ़ाना : अनुदान प्राप्त करने के लिए 17 शीर्ष आवेदकों में से 6 का चयन किया गया। इंक्यूबेशन केंद्रों को समर्थन बढ़ाने के लिए विस्तृत एमओए तैयार किया जा रहा है।<br>• अटल ग्रैड चुनौती : भारत की चुनौतियों के सक्षम, स्तरीय, लागत प्रभावी, विश्व स्तरीय समाधान के लिए उचित क्षेत्रों का मूल्यांकन अभी किया जा रहा है। |

***